ciency in an ever-changing technological and social environment. The proposals to effect changes in the present structure of postal divisions, etc., are in an initial stage of consideration and have not been finalised.

सूरत में विदेशी उप-डाकघर

362. श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूरत में स्थानीय जिला प्रशासन ने सूरत में विदेशी उप-डाकघर स्थापित करने हेतु आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, एक विदेश उप डाकघर के लिए निरंतर मांग को मद्देनजर रखते हुए और निर्यात को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों के एक भाग के रूप में, सूरत प्रधान डाकघर में 2-4-1994 को एक एक्सपोर्ट एक्सटेंशन विंडो खोली गई थी।

ग्रामीण क्षेत्र में डाक वितरण प्रणाली और अन्य डाक सेवाओं की समीक्षा

363. श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डाक बांटने और अन्य डाक सेवाओं के कार्य की समीक्षा की है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी हां। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में डाक-वितरण की क्षेत्रीय और मुख्यालय स्तर पर प्रणालीबद्ध मानीटरिंग और पुनरीक्षा करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य डाक सेवाओं की आवधिक जांच और पुनरीक्षा की जाती है।

डाकघर खोलने के औचित्य की जांच करने के लिए निरीक्षक स्टाफ के माध्यम से नियमित सर्वेक्षण कराने की भी प्रणाली है।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवायें सामान्यतया संतोषजनक हैं किन्तु परिवहन की अप्रत्याशित समस्याओं और विभाग के नियंत्रण से परे अन्य ऐसे कारणों की वजह से डाक वितरण में विलम्ब हो जाता है।

(ग) (i) डाक वितरण का पुनरीक्षा एक अनवरत प्रक्रिया है। डाक में विलम्ब के कारणों का, यदि कोई हो, विभिन्न स्तरों पर सर्वेक्षण करके पता लगाया जाता है।

(ii) नए डाकघर खोलकर डाक सेवाओं का उत्तरोत्तर विस्तार किया जा रहा है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों में, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 1302 शाखा डाकघर मंजूर किए किए गए।

Traffic control and management Information system in Andhra Pradesh

364. SHRI K. M. KHAN: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to refer to answer to Unstarred Question 9 given in the Rajya Sabha on the 14th February, 1995 and state:

(a) whether Government propose to expand Traffic Control Management Information system in Andhra Pradesh; and

(b) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) No, Sir.

(b) Does not arise. No such equipment has yet been standardised.